भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1356

उत्तर देने की तारीख 28 जुलाई, 2025

6 श्रावण, 1947 (शक)

जनजातीय युवाओं में प्रतिभा संवर्धन योजना

1356. श्री वीरेन्द्र सिंह:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के जनजातीय / वन क्षेत्रों के युवाओं की प्रतिभा को विकसित करने और उसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने की कोई योजना है;

(ख) क्या देश भर के जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन सुविधाओं के अभाव के कारण वे राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले पाते हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार की जनजातीय बहुल जिलों में खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के जनजातीय क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता के बावजूद तीरंदाजी, फुटबॉल, कबड्डी आदि खेलों के लिए कोई खेल मैदान / स्टेडियम नहीं है;

(च) यदि हाँ, तो क्या सरकार के पास इस संबंध में कोई योजना है और उक्त उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की जा रही है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ) जनजातीय और वन क्षेत्रों के युवाओं की प्रतिभा को निखारने और उनके कौशल व क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करने के लिए सरकार की कई स्कीमें और कार्यक्रम हैं। ये प्रयास विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा किए जाते हैं।

उदाहरण के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय विद्यार्थियों, लड़के और लड़कियों दोनों को उनके परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की केंद्रीय क्षेत्र स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है। ईएमआरएस को नवोदय विद्यालयों के समकक्ष बनाया जाएगा, जहाँ स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएँ

उपलब्ध होंगी, साथ ही खेलकूद और कौशल विकास में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ईएमआरएस के निर्माण के लिए 15 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी और इसमें कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाले समान संख्या में लड़के और लड़कियों सहित 480 छात्रों के रहने की क्षमता होगी। अब तक, 728 स्कूलों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से 479 ईएमआरएस देशभर में कार्यरत हैं। राज्य ईएमआरएस सोसायटियों के समन्वय से ईएमआरएस स्कीम के प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए एक स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा सोसाइटी (एनईएसटीएस) की स्थापना की गई है।

ईएमआरएस स्कूल छात्रों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देते हैं इसलिए विभिन्न ईएमआरएस स्कूलों के बीच साहसिक खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएँ, भ्रमण और आदान-प्रदान कार्यक्रम जैसी विभिन्न गतिविधियाँ नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। ईएमआरएस में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ शुरू की गई हैं, जैसे :-

1. एथलेटिक प्रतिभा को पोषित करने के लिए इनडोर और आउटडोर दोनों खेलों और खेल प्रशिक्षण के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास।
2. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहन और सहायता।
3. प्रत्येक वर्ष मंत्रालय ईएमआरएस छात्रों के लिए सांस्कृतिक सम्मेलन और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है, ताकि उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान करके पाठ्येत्तर गतिविधियों में प्रोत्साहित किया जा सके।

इसके अलावा, खेल राज्य का विषय होने के कारण राज्य में खेलों को बढ़ावा देना संबंधित राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी है। तथापि, राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने के लिए, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) देश भर में निम्नलिखित खेल प्रोत्साहन स्कीमें लागू कर रहा है ताकि विभिन्न आयु वर्गों में जमीनी स्तर पर जनजातीय युवाओं सहित प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की जा सके और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके :

- राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई)
- साई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी)
- एसटीसी का विस्तार केंद्र
- राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी)
  (इसकी उप-सकीमें - नियमित स्कूल, आईजीएमए और अखाड़े)

भारतीय खेल प्राधिकरण खेल प्रोत्साहन स्कीमों के अंतर्गत चिन्हित खिलाड़ी देश के ग्रामीण, जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों सहित समाज के सभी वर्गों से आते हैं और उन्हें स्कीमों के अनुमोदित मानदंडों के अनुसार आवासीय और गैर-आवासीय आधार पर नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

क्षेत्रीय केंद्र	**केंद्रों के नाम**	**राज्य**
गुवाहाटी	कोकराझार	असम

इम्फाल	ऐजवाल	मिजोरम
	दिमापुर	नागालैंड
कोलकाता	निकोबार	अंडमान और निकोबार
एलएनसीपीई	अंदरोथ	लक्षद्वीप

चयनित एथलीटों को अनुमोदित स्कीम मानदंडों के अनुसार विशेषज्ञ प्रशिक्षक, खेल उपकरण, वैज्ञानिक सहायता, भोजन और आवास, खेल किट, प्रतियोगिता प्रदर्शन, शैक्षिक व्यय, चिकित्सा/बीमा और वजीफा के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उपरोक्त के अलावा, साई खेल अवसंरचनाओं का उपयोग स्थानीय और जमीनी स्तर के एथलीटों द्वारा भी किया जा रहा है।साई खेल प्रोत्साहन स्कीमों के अंतर्गत, एथलीटों को जाति, पंथ, समुदाय आदि के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जाता है। चयनित एथलीटों को उन्नत प्रशिक्षण के लिए आधुनिक खेल उपकरण प्रदान किए जाते हैं। प्रतिस्पर्धी उत्कृष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से एथलीटों को विशेषज्ञ प्रशिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की देखरेख में नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है।

इसके अलावा, खेलो इंडिया स्कीम के दोहरे उद्देश्य जन भागीदारी और खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना हैं। इस स्कीम के तहत देश के जनजाति/वन क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए विभिन्न पहल शुरू की गई हैं। इसका घटक-वार विवरण इस प्रकार हैं:

1. खेलो इंडिया प्रतिभा पहचान और विकास: 21 खेल विधाओं (पैरा खेलों सहित) में 2808 एथलीटों को अधिसूचित किया गया है। खेलो इंडिया एथलीटों (केआईए) के प्रशिक्षण के लिए कुल 306 अकादमियों को मान्यता दी गई है। मान्यता प्राप्त खेल अकादमियों के अंतर्गत आवासीय खेलो इंडिया एथलीट (केआईए) के वित्तपोषण के मानदंडों के तहत प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष 6,28,400/- रु. की सहायता दी जाती है।

अब तक खेलो इंडिया गेम्स के 19 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 56000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया है, जिनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के एथलीट भी शामिल हैं। यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के एथलीटों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

2. खेलो इंडिया केंद्र और खेल अकादमियां:

क) खेलो इंडिया केंद्र (केआईसी): केआईसी की स्थापना इच्छुक बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करने, पूर्व चैंपियन एथलीटों (पीसीए) को कोच के रूप में आजीविका के अवसर प्रदान करने और मौजूदा अवसंरचनाओं के उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। अब तक, देश भर में 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 1057 केआईसी अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें से 966 केआईसी वर्तमान में कार्यरत हैं और 28,110 एथलीटों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

ख) केआईएससीई (खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र): 33 राज्यों में 34 केआईएससीई, 420 स्वीकृत जनशक्ति के साथ, जनशक्ति, खेल उपकरण और खेल विज्ञान उपकरणों की महत्वपूर्ण कमी को दूर करके, देश भर में 2244 एथलीटों के प्रशिक्षण को सुकर बना रहे हैं।

3. खेलों में समावेशिता : यह घटक सभी के लिए विशेष रूप से महिलाओं, दिव्यंगजनों, लाभवंचित समुदायों के लिए खेलों को सुलभ बनाने पर और ग्रामीण/देशज खेलों का प्रोत्साहन करने पर केंद्रित है।

(i) महिलाओं के लिए खेल: महिलाओं को खेल गतिविधियों में भाग लेने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने के लिए 2021 में खेलो इंडिया महिला लीग की शुरुआत की गई थी। इसका नाम बदलकर अस्मिता लीग कर दिया गया, जिसका अर्थ है "कार्यों के माध्यम से महिलाओं को प्रेरित करके खेल जगत में उपलब्धियाँ प्राप्त करना"। अब तक देश भर में 29 खेल विधाओं में महिला लीग का आयोजन किया जा चुका है। महिला एथलीटों के लिए कुल 1310 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा चुका है, जिनमें 138875 प्रतिभागियों ने भाग लिया है।

इसके अलावा, खेलो इंडिया स्कीम के तहत, खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य इच्छुक बच्चों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, कोच के रूप में पूर्व चैंपियन एथलीटों (पीसीए) को आजीविका के अवसर प्रदान करना और जनजातीय बहुल जिलों सहित देश भर में मौजूदा अवसंरचनों के उपयोग को बढ़ाना है।

इसका विवरण निम्नलिखित यूआरएल https://dashboard.kheloindia.gov.in पर उपलब्ध है:

(ङ) से (छ) साई केवल अपने साई केंद्रों में ही अवसंरचनाओं का निर्माण/उन्नयन करता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में कोई भी साई केंद्र कार्यशील नहीं है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में कुश्ती के लिए एक खेलो इंडिया केंद्र अधिसूचित किया गया है।

जिला	केआईसी का नाम	खेल विधा	पुरुष	महिला	कुल
चंदौली	श्री कृष्ण व्यायामशाला सेवा ट्रस्ट, करवट दांडी, चंदौली	कुश्ती	15	15	30

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और अन्य पात्र संस्थाओं से प्राप्त खेल अवसंरचना के निर्माण और उन्नयन प्रस्तावों पर वित्तीय सहायता के लिए उनकी पूर्णता, तकनीकी व्यवहार्यता तथा स्कीम के अंतर्गत धनराशि की उपलब्धता पर विचार किया जाता है।

अब तक, खेलो इंडिया स्कीम के "खेल अवसंरचना का निर्माण और उन्नयन" घटक के अंतर्गत देश भर में 328 खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें उत्तर प्रदेश राज्य में 31 परियोजनाएँ शामिल हैं।इसका विवरण https://mdsd.kheloindia.gov.in/ पर उपलब्ध हैं।

*****